

बिक्री कर (कानून) उप आयुक्त राजस्व (कर) मंडल, एर्नाकुलम

बनाम

आडवाणी ऑर्लिंकॉन (पी) लिमिटेड त्रिवेन्द्रम

12 अक्टूबर, 1979

[एन.एल. अंतवालिया और आर.एस. पाठक, जे.जे.]

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 2 (जे) और 2 (एच) -
दायरा

प्रतिवादी निर्धारिती एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के एक निश्चित ब्रांड के लिए एकमात्र बिक्री एजेंट के रूप में व्यवसाय करती है। इसने अच्छी आपूर्ति के लिए खुदरा विक्रेताओं से कैटलॉग मूल्य कम व्यापार छूट वसूल की। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत दाखिल रिटर्न में मूल्यांकन वर्ष 1971-72 के लिए अंतर-राज्यीय बिक्री का करयोग्य मूल्य रु. 871624/- दर्शाया गया है। यह आंकड़ा निर्धारिती द्वारा खुदरा विक्रेताओं को ट्रेड डिस्काउंट के रूप में भुगतान किए गए कैटलॉग मूल्य से रु. 1,06,708/- घटाकर निकाला गया था। बिक्री कर अधिकारी ने कटौती की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कर योग्य टर्नओवर की गणना 9,78,332/- रुपये की। अपील पर, अपीलीय सहायक आयुक्त ने निर्धारिती के दावे को बरकरार रखा कि

व्यापार छूट टर्नओवर का हिस्सा नहीं थी और इसलिए, बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता था। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दूसरी अपील खारिज कर दी गई। राजस्व द्वारा उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण आवेदन भी खारिज कर दिया गया।

यह तर्क दिया गया था कि (i) उच्च न्यायालय ने यह पुष्टि करने में गलती की है कि व्यापार छूट के माध्यम से भुगतान की गई राशि को मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए कर योग्य कारोबार में शामिल नहीं किया जा सकता है, (ii) वास्तव में निर्धारिती ने दो अलग-अलग अनुबंधों में प्रवेश किया है खुदरा विक्रेता के साथ, पहला अनुबंध कैटलॉग मूल्य पर माल की बिक्री से संबंधित था और दूसरे अनुबंध में यह निर्धारित किया गया था कि खुदरा विक्रेता वास्तव में बिक्री मूल्य कम व्यापार छूट का भुगतान कर सकता है, क्योंकि बिक्री पहले अनुबंध के तहत हुई थी, इसलिए पूरी राशि को माना जाएगा उस अनुबंध के तहत बिक्री पर प्रतिफल को कर योग्य टर्नओवर में शामिल किया जाना था।

अपील को खारिज करते हुए-

अभिनिर्धारित किया : यह सच है कि धारा 2(एच) द्वारा "बिक्री मूल्य" की परिभाषा में केवल नकद छूट के कारण कटौती पर विशेष रूप से बिक्री विचार से विचार किया गया है और नकद छूट को व्यापार छूट के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। वे दो अलग और विशिष्ट

अवधारणाएँ हैं। नकद छूट की अनुमति तब दी जाती है जब खरीदार तुरंत या स्वीकृत क्रेडिट अवधि के भीतर भुगतान करता है। यह शीघ्र भुगतान को ध्यान में रखते हुए दी गई छूट है। व्यापार छूट थोक विक्रेताओं द्वारा व्यापार में लगे खुदरा विक्रेताओं को अनुमत वस्तुओं की सूचीबद्ध कीमत से कटौती है। भत्ता खुदरा विक्रेता को सूचीबद्ध मूल्य पर सामान बेचने में सक्षम बनाता है और फिर भी उसके व्यावसायिक व्यय को ध्यान में रखने के बाद लाभ का उचित मार्जिन बनाता है। एक थोक व्यापारी द्वारा एक खुदरा विक्रेता को भेजा गया बाहरी चालान कैटलॉग मूल्य दिखाता है और फिर से व्यापार छूट में कटौती दिखाई जाती है। शुद्ध राशि बिक्री मूल्य है, और यह वह शुद्ध राशि है जो संबंधित पक्षों की पुस्तकों में वसूली योग्य राशि में दर्ज की जाती है। [933 जी एच. 934 ए-सी]

ओरिएंट पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य (1975) 35 एस टी सी 34 संदर्भित किया।

बिक्री कर अधिनियम के तहत, बिक्री मूल्य जो टर्नओवर की गणना में प्रवेश करता है वह वह प्रतिफल है जिसके लिए सामान निर्धारिती द्वारा बेचा जाता है, जहां कैटलॉग मूल्य पर व्यापार छूट की अनुमति है, बिक्री मूल्य कटौती के बाद निर्धारित राशि है व्यापार की छूट। यह सारहीन है कि अधिनियम की धारा 2(एच) में "बिक्री मूल्य" की परिभाषा स्पष्ट रूप से बिक्री मूल्य से व्यापार छूट की कटौती का प्रावधान नहीं करती है। इस

परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि बिक्री मूल्य व्यापार छूट में कटौती के बाद आता है, बिक्री मूल्य से व्यापार छूट के माध्यम से किसी भी सुज्म की कटौती का कोई सवाल ही नहीं उठता है। न ही यहां पक्षों के बीच दो क्रमिक समझौतों का कोई सवाल है, एक कैटलॉग मूल्य पर माल की बिक्री के लिए और दूसरा व्यापार छूट के माध्यम से भत्ते के लिए प्रदान करने का। व्यापार छूट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, डीलर और खुदरा विक्रेता के बीच केवल एक बिक्री मूल्य होता है और वह खुदरा विक्रेता द्वारा देय मूल्य है जिसकी गणना कैटलॉग मूल्य और व्यापार छूट के बीच के अंतर पर की जाती है। पक्षों के बीच केवल एक अनुबंध है, अनुबंध यह है कि सामान डीलर द्वारा खुदरा विक्रेता को उपरोक्त बिक्री मूल्य पर बेचा जाएगा। बिक्री मूल्य जो बिक्री कर अधिनियम के तहत मूल्यांकन के उद्देश्य से निर्धारिती के कारोबार की गणना में शामिल होता है, कैटलॉग मूल्य से व्यापार छूट घटाने के बाद प्राप्त किया जाता है। निर्धारिती द्वारा अनुमत व्यापार छूट को टर्नओवर में शामिल नहीं किया जा सकता है। [934 सी-ई, एफ,935]

ओरिएंट पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य (1975) 35 एसटीसी 84, अम्बिका मिल्स लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य (1964) 15 एसटीसी 367- पुष्टि की।

इंडिया पिस्टन्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य (1974) 33
एसटीसी 472, विशिष्ट।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1897/1976

केरल उच्च न्यायालय द्वारा टी. आर. सी. सं. 86/74 में पारित
निर्णय और आदेश दिनांक 24-10-1975 से उत्पन्न विशेष अनुमति द्वारा
अपील

डॉ. वी. ए. सैयद मुहम्मद और के. आर. नाम्बियार, अपीलार्थी की
ओर से।

डॉ. वाई. एस. चिताले और श्रीमती सुनंदा भंडारे, प्रतिवादी की ओर
से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया -

पाठक, न्यायाधिपति :

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील यह सवाल उठाती है कि क्या
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के तहत बिक्री कर के लिए निर्धारित
टर्नओवर की गणना के उद्देश्य से माल की बिक्री कीमत व्यापार छूट के
माध्यम से भुगतान की गई राशि को शामिल करके निर्धारित की जाती है।

निर्धारिती एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के एक निश्चित ब्रांड के लिए एकमात्र बिक्री एजेंट के रूप में व्यवसाय करती है। खुदरा विक्रेताओं को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के लिए, यह उनसे व्यापार छूट घटाकर कैटलॉग मूल्य वसूल करता था। कैटलॉग कीमत वह कीमत है जिसे खुदरा विक्रेता उपभोक्ता से वसूलने का हकदार है। आकलन वर्ष 1971-72 के लिए, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के तहत दाखिल किए गए रिटर्न में अंतर-राज्य बिक्री का कर योग्य कारोबार 8,71,624 रुपये दिखाया गया। यह आंकड़ा कैटलॉग मूल्य से खुदरा विक्रेताओं को निर्धारिती द्वारा व्यापार छूट के रूप में भुगतान की गई 1,06,708 रुपये की राशि को घटाकर निकाला गया था। बिक्री कर अधिकारी ने कटौती की अनुमति देने से इनकार कर दिया और करयोग्य टर्नओवर 9,78,332 रुपयेगणना की। बिक्री कर अधिकारी का विचार था कि व्यापार छूट के माध्यम से भुगतान की गई राशि को कैटलॉग मूल्य से बाहर नहीं किया जा सकता है। निर्धारिती ने अपील की, और अपीलीय सहायक आयुक्त ने उसके दावे को बरकरार रखा कि व्यापार छूट टर्नओवर का हिस्सा नहीं थी, और इसलिए इस पर बिक्री कर नहीं लग सकता। राजस्व द्वारा दायर दूसरी अपील अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दी गई थी। राजस्व ने केरल उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन किया और पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिया गया है। यह राजस्व अपील।

राजस्व द्वारा हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने यह पुष्टि करने में गलती की है कि व्यापार छूट के माध्यम से भुगतान की गई राशि को मूल्यांकन के उद्देश्य से कर योग्य कारोबार में शामिल नहीं किया जा सकता है। यह बताया गया है कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 2(एच) में "बिक्री मूल्य" की परिभाषा केवल नकद छूट के रूप में अनुमत राशि की कटौती की अनुमति देती है और व्यापार छूट के माध्यम से अनुमत राशि का कोई संदर्भ नहीं देती है। यह तर्क दिया गया है कि वास्तव में निर्धारित खुदरा विक्रेता के साथ दो अलग-अलग अनुबंधों में प्रवेश करता है, पहला अनुबंध कैटलॉग मूल्य पर माल की बिक्री से संबंधित है और दूसरा अनुबंध यह निर्धारित करता है कि पहले अनुबंध के तहत खुदरा विक्रेता के दायित्व के बावजूद, संपूर्ण भुगतान करना होगा बिक्री मूल्य, वह वास्तव में बिक्री मूल्य घटाकर व्यापार छूट का भुगतान कर सकता है। उस निवेदन पर, यह आग्रह किया जाना चाहिए कि चूंकि बिक्री पहले अनुबंध के तहत की गई है, इसलिए उस अनुबंध के तहत बिक्री के लिए प्रतिफल के रूप में मानी जाने वाली पूरी राशि को कर योग्य टर्नओवर में शामिल किया जाना चाहिए।

हमने मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हमारे निर्णय में अपील विफल होनी चाहिए।

शुरुआत में, यह उचित होगा कि हम केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम में निहित दो प्रासंगिक परिभाषाओं को सामने रखें। धारा 2 (जे) "टर्नओवर" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है "अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी भी सामान की बिक्री के संबंध में उसके (डीलर) द्वारा प्राप्त और प्राप्य बिक्री मूल्यों का कुल योग", और अधिनियम की धारा 2 (एच) अभिव्यक्ति "बिक्री मूल्य" को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है "किसी भी सामान की बिक्री के लिए डीलर को देय राशि, सामान्य रूप से प्रचलित प्रथा के अनुसार नकद छूट के रूप में दी गई किसी भी राशि को घटाकर व्यापार"। यह सच है कि धारा 2 (एच) द्वारा "बिक्री मूल्य" की परिभाषा में बिक्री विचार से नकद छूट के कारण कटौती पर विशेष रूप से विचार किया गया है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि नकद छूट को व्यापार छूट के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। दोनों अवधारणाएँ पूरी तरह से अलग और अलग हैं। नकद छूट की अनुमति तब दी जाती है जब खरीदार तुरंत या क्रेडिट की अनुमति की अवधि के भीतर भुगतान करता है। यह शीघ्र भुगतान को ध्यान में रखते हुए दी गई छूट है। व्यापार छूट थोक विक्रेताओं द्वारा व्यापार में लगे खुदरा विक्रेताओं को अनुमत वस्तुओं की सूची मूल्य से कटौती है। भत्ता खुदरा विक्रेता को कैटलॉग मूल्य पर सामान बेचने में सक्षम बनाता है और फिर भी अपने व्यावसायिक व्यय को ध्यान में रखते हुए लाभ का उचित मार्जिन कमाता है। एक थोक व्यापारी द्वारा खुदरा विक्रेता को भेजा गया बाहरी चालान

कैटलॉग मूल्य दिखाता है और उसके विरुद्ध व्यापार छूट की कटौती दिखाई जाती है। शुद्ध राशि बिक्री मूल्य है, और यह वह शुद्ध राशि है जो संबंधित पक्षों की पुस्तकों में वसूली योग्य राशि के रूप में दर्ज की जाती है। ओरिएंट पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य ⁽¹⁾।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत, बिक्री मूल्य जो टर्नओवर की गणना में शामिल होता है वह वह विचार है जिसके लिए करदाता द्वारा सामान बेचा जाता है। ऐसे मामले में जहां सूची मूल्य पर व्यापार छूट की अनुमति है, बिक्री मूल्य वह राशि है जो व्यापार छूट में कटौती के बाद निर्धारित की जाती है। व्यापार छूट बिक्री मूल्य की संरचना में प्रवेश नहीं करती है, लेकिन इससे अलग और उससे पहले मौजूद है। यह कोई मायने नहीं रखता कि अधिनियम की धारा 2 (एच) में "बिक्री मूल्य" की परिभाषा बिक्री मूल्य से व्यापार छूट की कटौती के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं करती है। वास्तव में, इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि बिक्री मूल्य व्यापार छूट में कटौती के बाद प्राप्त होता है, व्यापार छूट के माध्यम से बिक्री मूल्य से किसी भी राशि को काटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।

न ही यहां पार्टियों के बीच दो क्रमिक समझौतों का कोई सवाल है, एक कैटलॉग मूल्य पर माल की बिक्री प्रदान करता है और दूसरा व्यापार छूट के माध्यम से भत्ता प्रदान करता है। व्यापार छूट की प्रकृति को ध्यान

में रखते हुए, डीलर और खुदरा विक्रेता के बीच केवल एक बिक्री मूल्य होता है, और वह खुदरा विक्रेता द्वारा देय मूल्य है जिसकी गणना कैटलॉग मूल्य और व्यापार छूट के बीच अंतर के रूप में की जाती है। पार्टियों के बीच केवल एक अनुबंध है, अनुबंध यह है कि सामान डीलर द्वारा खुदरा विक्रेता को उपरोक्त बिक्री मूल्य पर बेचा जाएगा।

हमारे समक्ष अंबिका मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य ⁽²⁾ के मामले को संदर्भित किया गया है, जहां गुजरात उच्च न्यायालय ने माल की डिलीवरी के समय कीमतों में सामान्य गिरावट के कारण खरीदार को बिक्री मूल्य से अनुमत छूट की कटौती के निर्माता के दावे को खारिज कर दिया। हमारी राय में, मामला उस दृष्टिकोण का समर्थन करता है जो हम ले रहे हैं। बिक्री मूल्य पक्षों के बीच अनुबंध में निर्धारित मूल्य बना रहा। कीमतों में कमी बिक्री के अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने के बाद हुई, और खरीदार को कुछ हद तक नुकसान से राहत देने की दृष्टि से इस प्रकार जो हो सकता था, निर्माता ने खरीदार को छूट या छूट देकर नुकसान का कुछ हिस्सा वहन करने की मांग की। राजस्व ने इंडिया पिस्टन्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य ⁽¹⁾ पर भरोसा किया। उस मामले में, करदाता द्वारा टर्नओवर से जिस बोनस की कटौती की मांग की गई थी, उसका भुगतान बोनस छूट योजना के तहत किया गया था, सभी ग्राहकों को नहीं, बल्कि केवल उन वितरकों को जिनकी करदाता से शुद्ध

खरीद पार्टियों के बीच सहमत लक्ष्य आंकड़े से अधिक थी। अनुमत छूट की राशि ग्राहक के खाते में जमा की जाती थी और इसे एक आरक्षित राशि के रूप में माना जाता था जिससे वितरक भविष्य में खरीदारी कर सकते थे। बोनस छूट की छूट को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी गई थी और, हमारी राय में, यह सही है। यह उन वितरकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन बोनस की प्रकृति में था जिनकी शुद्ध खरीद लक्ष्य के आंकड़े से अधिक थी। यह निर्धारिती द्वारा बेची गई वस्तुओं के बिक्री मूल्य को प्रभावित नहीं करता था और न ही कर सकता था। पक्षकारों के बीच अनुबंध में बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहा।

हमारे निर्णय में, बिक्री मूल्य जो केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत मूल्यांकन के उद्देश्य से निर्धारिती के कारोबार की गणना में शामिल होता है, कैटलॉग मूल्य से व्यापार छूट घटाने के बाद प्राप्त किया जाता है। निर्धारिती द्वारा अनुमत व्यापार छूट को टर्नओवर में शामिल नहीं किया जा सकता है।

परिणामस्वरूप, अपील विफल हो जाती है और लागत के साथ खारिज कर दी जाती है।

एन के ए

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।